# सीरिया में फ्रांसीसी संरक्षण

प्रथम विश्वयुद्ध के समय से ही फ्रांस सीरिया तथा लेबनान के क्षेत्रों पर अपनी दृष्टि जमाए हुए था। 1916 के साइक्स-पिकोट समझौते के अनुसार यह तय हुआ था कि सीरिया और लेबनान के क्षेत्र में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना की जाएगी। 1918 में जब युद्ध की समाप्ति हुई, उस समय सीरिया और लेबनान पर मित्रराष्ट्रों की सेना का अधिकार था। ब्रिटेन इन क्षेत्रों पर भी अपना अधिकार कायम करना चाहता था, पर साइक्स-पिकोट समझौते के अनुसार वह ऐसा नहीं कर सकता था।

ब्रिटेन ने एक कूटनीतिक चाल चली। उसने अपने विश्वस्त मित्र अमीर फैजल को सीरिया पर कब्जा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 3 अक्टूबर 1918 को फैजल अपनी सेना के साथ दमिश्क पहुंचा और ब्रिटिश और अधिकारियों की सहायता से सीरिया में एक स्वतंत्र सरकार की स्थापना की घोषणा कर दी। इस प्रकार सीरिया के समुद्री तटों पर फ्रांसीसी सैनिकों का अधिकार था और अन्दर के हिस्से में फैजल का शासन स्थापित हो गया।

## पेरिस के शांति सम्मेलन

में फ्रांसीसी प्रतिनिधि-मंडल ने सीरिया और लेबनान पर अपना दावा प्रस्तुत किया पर अन्य दिशाओं से इसका विरोध हुआ। विल्सन ने फ्रांसीसी दावे को आत्मनिर्णय के सिद्धान्त का विरोधी माना। लायड जार्ज ने कहा कि ऐसा मान लेना अरबों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। सीरिया के लोग इसका जबर्दस्त विरोध कर रहे थे। 1919 के अंत में सीरिया से ब्रिटिश सेना के हट जाने के बाद मार्च 1920 में दमिश्क के एक सम्मेलन में सीरिया पर फ्रांसीसी आधिपत्य का घोर विरोध किया गया और फैजल को सीरिया का राजा घोषित कर दिया गया।

परन्तु फ्रांस सीरिया तथा लेबनान पर अपने दावे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। इसी बीच अप्रैल 1920 को सेनरेमो का सम्मेलन हुआ। सेनरेमो सम्मेलन ने सीरिया और लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण की स्थापना का निर्णय लिया।

इस निर्णय के विरुद्ध सीरिया में विद्रोह हो गया। विद्रोहियों ने इतनी अशान्ति फैला दी कि फ्रांसीसियों के लिए सीरिया - - - -

अगला Page

पर कब्जा करना कठिन हो गया। इसी क्रम में अरबों और फ्रांसीसियों के बीच झड़पें हो गईं। इसका लाभ उठाकर फ्रांसीसियों ने सीरिया पर आक्रमण कर दिया। फ्रांसीसी सेनापति जनरल गुरो ने 14 जुलाई 1920 को फैसल को चेतावनी देते हुए सीरिया पर कब्जा कर लिया। इसके साथ ही सीरिया पर फैसल के शासन का अंत हो गया और सीरिया फ्रांस के अधीन हो गया। 1923 में राष्ट्रसंघ ने भी सीरिया तथा लेबनान पर फ्रांसीसी संरक्षण का अनुमोदन कर दिया।

सीरिया में फ्रांस का संरक्षण काल को सुविधा के दृष्टिकोण से तीन कालों में बाँटकर अध्ययन किया जा सकता है —

फ्रांसीसी संरक्षण का पहला काल — (1920-26 ई०)

इस समय सीरिया और लेबनान की जनता फ्रांस के सैनिक शासन से असंतुष्ट रही और यत्र-तत्र बगावत करती रही। इस काल में फ्रांस की तीन व्यक्तियों — गुरोद (Gouraud), वेगैंड (weygand) तथा सरायल (Sarrail) सेना के अफसर थे उन्होंने सैनिक शासन (कानून) लागू रखा और राष्ट्रीयता की भावनाओं को कुचल कर रख दिया। इस काल को भूल व बर्बादी का काल कहा गया है, जिसमें मैंडेट के प्रशासकों ने "अशांति के बीज" बोये और विद्रोह की फसल काटी। फ्रेंच अधिकारियों ने प्रेस और प्रचार के साधनों

अपना नियंत्रण स्थापित किया। राष्ट्रीयता और सीरिया की एकता-सम्बन्धी सभी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। राज्य के अन्तर्गत विभिन्न जातियों के बीच द्वेष एवं भेदभाव का बीजारोपण किया। इसके साथ ही आम निर्वाचन में भी इन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप किया तथा अपने उम्मीदवारों का पक्ष लिया। 1921 में जेबलड्रूज और 1922 में अलावी (Alawis) को स्वतंत्र मान लिया गया। इसके बावजूद भी फ्रेंच अधिकारी संतुष्ट नहीं थे।

उन्होंने सीरिया की अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक आधारों पर भी चोट की। इस समय सीरिया की मुद्रा-पद्धति में आमूल परिवर्तन लाया गया और एक नई लेबनान-सीरिया मुद्रा चालू की गई जिसे फ्रांसीसी मुद्रा फ्रेंक से आबद्ध कर दिया गया और इसके संचालन की जिम्मेवारी एक फ्रेंच बैंक को दी गई। इस काल में फ्रेन्च मुद्रा की कीमतों का ह्रास हुआ था। अतः सीरियाई मुद्रा की कीमत भी घट गई। इसके साथ ही एकाधिकार अनेक व्यावसायिक सुविधाओं के मामले में फ्रेंच नागरिकों एवं व्यापारियों को प्राथमिकता दी गई जिसका परिणाम यह हुआ कि सीरिया का व्यवसायी वर्ग क्षुब्ध हो गया। संस्कृति क्षेत्र में भी फ्रेंच शासनाधिकारियों ने चोटें कीं तथा फ्रेंच भाषा को अरबी के साथ-साथ राजकीय भाषा घोषित कर दिया। न्यायालयों तथा शिक्षण संस्थाओं में फ्रेंच भाषा को स्थान दिया

गया एवं प्राथमिक विद्यालयों में इसकी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई इस काल में अधिकांश प्रशासनिक अधिकारी फ्रेंच थे अतः फ्रेंच भाषा ही प्रमुख माध्यम बन गई और अरबी का स्थान गौण हो गया। अरब संस्थाओं की भी उपेक्षा की जाने लगी और नवीन फ्रेंच संस्थाओं को संगठित किया गया। वास्तव में मैंडेट को राष्ट्रसंघ ने पिछड़े देशों की प्रशासनिक शिक्षा के लिए स्थापित किया था। परंतु फ्रांस ने इसके साथ उपनिवेशों का सा व्यवहार किया। परिणामस्वरूप जनरल सरायल के शासन काल में जुलाई 1925 ई० में विस्फोट हो गया।

इस विद्रोह का आरंभ जबल-अलद्रूज में हुआ। ड्रूज कबीलों के सरदारों ने फ्रेंच दुर्व्यवहार से तंग आकर जुलाई, 1925 में फ्रेंच दफ्तरों पर आक्रमण कर दिया। इस विद्रोह ने शीघ्र ही राष्ट्रीय आंदोलन का रूप धारण कर लिया और इसका नारा एकता एवं स्वतंत्रता हो गया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता डॉ शाहबंदर, फारिस बेअल खुरी एवं सुल्तान अल अतरस के परिवार के थे इन्होंने दो फ्रेंच टुकड़ियों को परास्त कर दिया तथा दमिश्क सहित कई इलाकों जैसे होम्स, हामा, सुवैदा, अलेप्पो आदि पर कब्जा जमा लिया। इनकी सफलता से फ्रेंच फौज अधिकारी घबरा उठे। अक्टूबर 1925 ई० में दमिश्क पर भीषण गोलाबारी की गई। इससे धन-जन की अपार हानि हुई और जनरल

सरायल इतना अलोकप्रिय हो गया कि उसे वापस फ्रांस बुला लिया गया। उसका स्थान हेनरी डी जुवेनल ने लिया, पर उसे भी सीरिया में शांति स्थापना में सफलता नहीं मिली। अतः अगस्त, 1926 में एक सैनिक अधिकारी एम० पोंसोट को सीरिया का नया हाई कमिश्नर बनाकर भेजा गया। पोंसोट ने सीरिया के राष्ट्रवादी नेताओं के साथ वार्तालाप शुरू किया और विद्रोह को सफलता पूर्वक दबाया। 1926 में लेबनान में एक गणतंत्र की स्थापना की गई और यह कहा गया कि सीरिया के राष्ट्रीय नेता एक ऐसे संविधान का निर्माण करें जो सीरिया के सभी वर्गों को स्वीकार हो।

दूसरा काल (1926 - 1939) -

फ्रांसीसी
संरक्षण का दूसरा काल 1926 से प्रारंभ हुआ। इस समय एम० पोंसोट (M. Ponsont) उच्चायुक्त के पद पर बहाल होकर सीरिया तथा लेबनान भेजे गए। उच्चायुक्त पद संभालते ही उसने सार्वजनिक क्षमा (Amnesty) की घोषणा की। उसने देखा कि सीरिया वालों को नियंत्रित करना मुश्किल है। अतः फ्रांसीसी सरकार ने लेबनान में 1926 में एक रिपब्लिक सरकार की स्थापना कर दी उसका विचार था कि सीरिया वाले एक शासन विधान तैयार करें और उनका संसदीय शासन शुरू हो।

अप्रैल 1928 में फ्रांस ने सीरिया में संसद निर्माण के लिए चुनाव कराया और निर्वाचित संसद को एक संविधान बनाने के लिए कहा। 7 अगस्त को संसद ने एक संविधान की रूपरेखा तैयार की जिसमें फिलिस्तीन, ट्रांस-जोर्डन और लेबनान को सीरिया में सम्मिलित कर संयुक्त सीरिया का प्रबंध किया गया। इसकी सुरक्षा और विदेश नीति भी फ्रांस से मुक्त थी। संसद के पहले अधिवेशन में ही फ्रेंच मैंडेट का विरोध किया गया।

विधान के अध्ययनोपरांत फ्रांस ने महसूस किया कि इसमें फ्रांसीसी हित पर ध्यान नहीं दिया गया है अतः 1930 ई० में फ्रांस ने संसद को भंग कर अपनी ओर से मई 1930 में एक संविधान बनाया। इसकी प्रमुख विशेषताएं थीं—

1) एक संसद की स्थापना की जाए जिसका कार्यकाल 4 वर्ष हो
2) एक राष्ट्रपति की नियुक्ति होगी जो हमेशा मुसलमान होगा
3) सीरिया की विदेश नीति निर्धारित करने का अधिकार फ्रांस का होगा।

इस प्रकार सीरिया को गणराज्य का रूप दिया गया। कुछ विरोध और प्रदर्शन के बाद सीरिया वालों ने इसे स्वीकार कर लिया।

1932 में इस संविधान

के अनुसार चुनाव हुआ। 1933ई० में फ्रांस में एक प्रस्ताव रखा जिसमें निम्नलिखित शर्तें रखी गई —
(क) सीरिया को एक स्वतंत्र राष्ट्र स्वीकार किया जाए
(ख) उसे राष्ट्रसंघ का सदस्य बना लिया जाए तथा
(ग) 25 वर्ष तक सीरिया की राजनीतिक, आर्थिक तथा विदेश नीति पर फ्रांस का नियंत्रण रहे।

सीरिया की संसद ने इसे मानने से इंकार कर दिया और वहाँ राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गया।

सीरिया में राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव हुआ। इसमें अल-कुतला और अल-वतानिया मुख्य थे। बाद में इसका दल दो भागों में बंट गया अल-हिज्ब अल-वतनी (राष्ट्रीय पार्टी) और अल-हिज्ब अल-शाब (जनता पार्टी)।

अक्टूबर 1933 ई० में पोसोट का स्थान नवीन हाई कमिश्नर काउंट डी० मार्टेल ने लिया। उसने व्यवस्थापिका सभा को समाप्त कर सारी शक्ति अपने हाथ में केंद्रित कर ली। राष्ट्रवादियों का आंदोलन जारी रहा। अंततः 25 फरवरी 1936 ई० को सभी राष्ट्रवादी नेताओं को मुक्त कर, संधि के लिए आमंत्रित किया गया।

मार्च 1936 ई० में 6 राष्ट्रवादी सदस्यों का एक मंडल हाशिम-बे-अल अतासी की अध्यक्षता में पेरिस गया तथा वहाँ पर

यहाँ से — 9 सितम्बर, 1936 ई० को फ्रेंच-सीरियन संधि हुई जिसे 25 वर्षों के लिए लागू माना गया। इसकी प्रमुख शर्तें थीं —

1) जेबलड्रूज और लताकिया को सीरिया के अधीन किया गया, पर इनके लिए पृथक शासन की व्यवस्था की गई।

2) सीरिया की एकता को कायम रखने का वचन दिया गया।

3) सीरिया के दो हवाई अड्डों पर फ्रांस का अधिकार कायम किया गया। यह भी कहा गया कि लताकिया तथा जेबलड्रूज में पाँच साल तक फ्रेंच सेनाएँ रहेंगी। यह भी कहा गया कि सीरिया की सरकार सभी प्रकार की सुविधाएँ फ्रेंच सेना को देगी।

4) फ्रांस के दूतावास सीरिया में कायम रहेंगे जहाँ फ्रांस का राजदूत रहेगा। इसे सीरिया की सरकार अन्य राजदूतों की अपेक्षा अधिक आदर और सम्मान देगी।

5) तीन वर्ष के अंदर फ्रांस सीरिया को राष्ट्रसंघ का सदस्य बनाने में मदद करेगा। (Last Page)

उपर्युक्त संधि के अनुरूप ही 13 नवम्बर 1936 को लेबनान के साथ भी एक संधि की गई। इन दोनों संधियों की शर्तों को तीन वर्ष

पश्चात् कार्यान्वित करने की घोषणा की गई। संधि के आधार पर सीरिया में संसद का चुनाव हुआ और राष्ट्रीय नेताओं की विजय हुई। परन्तु लेबनान की जनता इस संधि से प्रसन्न नहीं हुई और असंतोष का वातावरण पुनः एक बार तैयार हो गया। लताकिया, जेबलड्रूज, केरक इत्यादि में पुनः विद्रोह हुए। लताकिया और जेबल ड्रूज की जनता सीरिया के साथ नहीं रहना चाहती थी। फ्रेंच सरकार ने यह आवश्यक समझा कि अलेक्जेंड्रिया को पृथक कर अभी एक स्वतंत्र राज्य के रूप में परिणत कर दिया जाए। फलतः 1937 में इसे सीरिया से अलग कर दिया गया और इसे एक पृथक राज्य का रूप दे दिया गया। फ्रांस तथा टर्की ने इसकी सुरक्षा की गारंटी दे दी। इस राज्य को हयाती का गणतंत्र (Republic of Hayati) कहा गया। अंत में यह गणतंत्र 2 जून 1939 को टर्की को सौंप दिया दिया गया। सीरिया के विभाजन की इस नीति का सीरियावालों ने घोर विरोध किया और राष्ट्रवादी उपद्रव पुनः प्रारंभ हो गया।

→ इस संधि के तुरंत पश्चात 1936 ई० के अंत में सीरिया में आम निर्वाचन हुआ जिसमें राष्ट्रवादियों की विजय हुई और हासिम-अल-अतासी नए राष्ट्रपति निर्वाचित हुए और जमील मर्दन-बे प्रधानमंत्री बने। नवीन संसद ने फ्रेंच-सीरिया संधि को अंतिम स्वीकृति दे दी और जबलअल द्रूज तथा लताकिया को सीरिया में मिला लिया। हाई कमिश्नर ने बहुत से प्रशासनिक कार्यों को नई सरकार के हाथ में देना आरंभ कर दिया। इस प्रकार राष्ट्रवादियों का लक्ष्य पूर्ण होता दिखाई देने लगा।

तीसरा काल - (1939 - 1964) - इस समय फ्रांस में नया मंत्रीमंडल बना और प्रधानमंत्री ब्लम ने (Blum) ने त्यागपत्र दे दिया। इस नए मंत्रीमंडल का कहना था कि सीरिया और लेबनान पर अन्य यूरोपीय राज्यों की अपेक्षा फ्रांस का अधिकार और प्रभाव अधिक है। इस समय युद्ध की संभावना नजर आ रही थी और सीरिया और लेबनान को फ्रांस के अधिकार में रखना अधिक आवश्यक होगा। क्योंकि युद्ध के समय इन प्रदेशों के हवाई अड्डे और आवागमन के साधनों का उपयोग किया जा सके।

इसी समय फ्रांस ने 1936 की

संधि का अनुमोदन नहीं किया, फलस्वरूप सीरिया वाले नाराज हो गए। फलस्वरूप 7 जुलाई 1939 को सीरिया के राष्ट्रपति हाशीम-अल-अतासी ने फ्रांसीसी नीति के विरोध में पद त्याग कर दिया।

फ्रांस की राजनीति में नया मोड़ आया। फ्रेंच हाईकमिश्नर गेब्रियल पावो (Gabriel Pueaux) का निरंकुश शासन शुरू हो गया। उसने सीरिया में निरंकुश शासन शुरू किया संसद को भंग कर दिया। अपने अधीन एक गैर-राजनीतिक निदेशक परिषद् (Council of Directors) की नियुक्ति की।

इसी बीच ~~1936~~ 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध छिड़ गया और फ्रांस ने सीरिया को अपने साम्राज्यवाद के चंगुल में जकड़ लिया। युद्ध काल में स्वतंत्रता-आंदोलन को अवैध घोषित कर दिया गया और एक विशाल फ्रेन्च फौज, जेनरल वेगाँड की अध्यक्षता में सीरिया में रख दी गई। परंतु 1940 ई० में फ्रांस का पतन हो गया।

~~कालक्रम में नयी परिस्थिति~~